एम. डी. मोइनूद्दीनन और अन्य

बनाम

सहयोग आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5448/2014)

7 मई, 2014

[सुरिंदर सिंह निजार और

फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

सहकारी समितियाँ-समूह-आवास सहकारी समिति-प्रारंभ में 28 सदस्यों वाली, 75 सदस्यों तक बढ़ती हुई-प्रारंभ में 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए धन से खरीदी गई भूमि-37 सदस्यों की सदस्यता विवादित-भूमि में विशेष अधिकार के लिए 11 संस्थापक सदस्यों का दावा, क्योंकि इसे उनके द्वारा प्रदान किए गए धन से खरीदा गया था-आयोजित किया गयाःव्यक्तिगत सदस्यों द्वारा दावा स्वीकार्य नहीं है-एक बार सोसायटी द्वारा भूमि खरीदे जाने के बाद, संपत्ति सोसाइटी में निहित हो जाती है-यह सोसाइटी का काम है कि वह सहकारी सिद्धांतों और उन उद्देश्यों के अनुसार भूमि के साथ व्यवहार करे जिनके साथ सोसाइटी का गठन किया गया था-सोसाइटी के सामान्य निकाय को निर्देश कि सदस्यों को उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए भूखंडों के आवंटन पर विचार किया जाए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1. 37 सदस्यों का प्रवेश अब विवाद में नहीं रह सकता है क्योंकि यह एक अंतिम मुद्दा था। यदि 37 व्यक्तियों की सदस्यता रद्द की जानी थी, तो सहकारी समिति

के उपनियमों में से किसी भी प्रासंगिक प्रावधान को लागू करके ऐसा किया जा सकता था। 37 सदस्यों में से 10 ने अपनी शेयर पूंजी की वापसी स्वीकार कर ली है और आज तक 37 में से केवल 27 ही बचे हैं जिन्होंने सोसायटी द्वारा जारी किए गए चेक वापस कर दिए हैं। नए जोड़े गए सदस्यों के निष्कासन से संबंधित पंजीयक द्वारा अनुमोदन के ऐसे किसी वैध आदेश की अनुपस्थिति में में, शेष 27 सदस्यों के सोसायटी के सदस्य नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है। [पैरा 29,30 और 31] [253-बी-एच]

2. समाज में अपने धन का योगदान करने वाले सदस्यों को इस आधार पर संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि उन्होंने भूमि की खरीद के लिए निवेश किया था। इस तरह का दावा सहकारी सिद्धांतों के विपरीत होगा, जो समाज के गठन के समय इसका उद्देश्य है। एक बार जब सोसायटी द्वारा भूमि खरीदी जाती है, तो संपत्ति सोसाइटी में निहित हो जाती है। इसलिए, यह समाज को इस बात पर विचार करना है कि सहकारी सिद्धांतों और उन उद्देश्यों के अनुसार उक्त भूमि से कैसे निपटा जाए जिनके साथ समाज का गठन किया गया था जैसा कि उप-कानूनों में उल्लेख किया गया है। यह व्यक्तिगत सदस्यों का दावा नहीं है कि भूमि को उसके सदस्यों के बीच वितरण के उद्देश्य से किस तरह से निपटाया जाना चाहिए। [पारस 35 और 36] [257-डी-एच]

3. इसलिए, न तो संस्थापक सदस्य और न ही जिन्हें बाद में सदस्यों के रूप में शामिल/भर्ती किया गया था, वे किसी विशेष तरीके से किसी भी वरीयता या आवंटन के अधिकार का दावा कर सकते हैं, इसके अलावा कि लेआउट को मंजूरी दिए जाने के बाद, सामान्य निकाय भूखंडों के आवंटन से संबंधित उपनियमों के अनुसार उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सोसायटी के सदस्यों के पक्ष में भूखंडों के आवंटन पर विचार करेगा। [पारस 38 और 39] [258-एच; 29-ए, सी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल याचिका संख्या 5448/2014

उच्च न्यायालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रिट अपील संख्या 798/2007 में दिनांकित 15.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2014 की सीए सं. 5451, 5449, 5450, 2011 की अवमानना पीटीशन सं. 251 और 2010 की अवमानना पीटीशन सं. 303

श्री ए. टी. एम. रंगरामुजम, आर. बसंत, जयदीप गुप्ता, सुश्री नेहा शर्मा, डी. वर्मा, एवी रंगम, बडी ए. रंगनाथन, जीवी। गिरिधर, डी. महेश बाबू, सुश्री सुचित्रा हरंगखॉल, अमजिद मकबूल, अमित के. नैन, आदित्य जैन, रामकृष्ण राव, गौरव अग्रवाल, अनूप कुमार, सुश्री नेहा जैसवाल, देवव्रत, सुश्री कस्तूरिका कौमुदी, श्रीमती के. शारदा देवी, अनुराग पांडे, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., राहल बंसल, गगनदीप शर्मा, निखिल जैन, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

के. श्रीनिवास राव, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

न्यायालय का निर्णय फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे द्वारा दिया गया था।

1. देरी को माफ कर दिया गया। अनुमति अनुदत्त गई।

2. उपरोक्त सभी अपीलों और संबंधित अवमानना याचिकाओं में, मुद्दा 'द वोल्टास एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड' नामक एक सहकारी समिति के सदस्यों से संबंधित है। यह एक क्लासिक मामला है जिसमें उपरोक्त संदर्भित समाज के सदस्य खुद को मुकदमों की एक श्रृंखला में उलझाते हैं और इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के सहकारी समिति विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसने विभिन्न समय पर पारित अलग-अलग आदेशों के

कारण हंगामा पैदा कर दिया है और इसलिए, इस न्यायालय के विचार की आवश्यकता है कि वह उचित आदेश पारित करे और इस जटिल मुकदमेबाजी को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त करे। समाज के सदस्यों के बीच पूरा विवाद भूमि के एक टुकड़े से संबंधित है, जिसे समाज द्वारा अपने सदस्यों को आवास प्रदान करने के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में खरीदा गया था। इस मुकदमे में उठाए गए विवाद में गहराई से जाने से पहले, हमारे समक्ष दायर विभिन्न विशेष अनुमति याचिकाओं को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा आदेशों को चुनौती दी गई है, जो अंततः, जैसा कि हमने बताया है, आवास प्रदान करने के लिए सोसायटी द्वारा खरीदी गई भूमि से संबंधित मुद्दे से संबंधित है।

3. सिविल अपील (2010 की @एस. एल. पी. (सी.) सं॰ 4679) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के 2007 की रिट अपील सं॰ 144 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया है, जो कि वोल्टास एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस 3 बिल्डिंग सोसाइटी (जिसे इसके बाद 'सोसाइटी' कहा गया है) है। सिविल अपील (2010 की @एस. एल. पी. (सी) सं॰ 3105) तीन व्यक्तियों, श्री एम. बालाजी, बिलकिस सुल्ताना और कोंडा सुरेका द्वारा दायर की गई है, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष 2007 की रिट अपील सं॰ 809 में अपीलकर्ता थे और जिनकी रिट अपील को उच्च न्यायालय द्वारा 2007 की रिट अपील सं॰ 144 के साथ अपने सामान्य निर्णय दिनांक 15.09.2009 में भी खारिज कर दिया गया था।

4. 2011 के एस. एल. पी. (सी. सी.) सं॰ 10023 को चार व्यक्तियों, अर्थात् नेरेला वेंकटेश्वरलू, एस. जगदीश, पासुपुला अंजनेयुलु और शनिगरपु रमेश ने 2007 के रिट अपील सं॰ 144 में अंतिम निर्णय और दिनांक 15.09.2009 के आदेश के साथ-साथ उक्त रिट अपील में 2009 के रिट अपील (एम. पी.) सं॰ 2325 के खिलाफ अपील

दायर करने के लिए इस अदालत की अनुमति मांगी है। खण्ड पीठ ने 2007 की रिट अपील को अपने सामान्य आदेश द्वारा खारिज करते हुए 2009 की उपरोक्त विविध याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता खुद को रिट अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल करना चाहते थे।

5. सिविल अपील (2010 का @एस. एल. पी. (सी) सं॰ 692) पाँच व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिनके नाम मो. मोइनुद्दीन, ए नरसिम्हा, मो. आई. शरीफ, खलंदर हुसैन और आर. शंकर ने 2007 की रिट अपील सं॰ 798 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांकित 15.09.2009 के सामान्य फैसले को 2007 की रिट अपील 4 सं॰ 144 और 2007 की 809 के साथ चुनौती देने की मांग की।

6. तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए, वोल्टास एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड को 1964 के आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 7 के तहत 29.10.1982 पर पंजीकृत किया गया था। इसका पता 4-161, माधवी नगर, फिरोजगुडा, हैदराबाद था। इसका संचालन हैदराबाद की नगरपालिका सीमाओं तक ही सीमित था। समाज का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार भूमि की खरीद, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना और विकास सहित भवन निर्माण के क्षेत्र में अपने सदस्यों के लाभ के लिए गतिविधियों को जारी रखना और अपने सदस्यों को आवास निर्माण के लिए ऋण देना भी है। उप-कानून संख्या 4 के तहत, सोसायटी की शेयर पूंजी प्रत्येक Rs.100 के 5000 शेयरों से बनी होनी थी। उप-कानून संख्या 5 किसी सदस्य की पात्रता निर्धारित करता है। उप-कानून संख्या 6 इस प्रक्रिया से संबंधित है कि वोल्टास का एक योग्य कर्मचारी समाज का सदस्य कैसे बन सकता है। उप-कानून संख्या 8 अपने उप-खंड (i) से (iv) के साथ सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है। उपनियम सं॰ 12 शेयर पूँजी की निकासी की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उप-कानून सं॰ 16 में वर्णन किया गया है कि किसी सदस्य को समाज से

कैसे निकाला जा सकता है। उप-कानून सं॰ 17 उन विभिन्न स्रोतों को सूचीबद्ध करता है जिनके द्वारा सोसायटी सामान्य रूप से धन प्राप्त कर सकती है। उप-कानून सं॰ 22 में कहा गया है कि प्रबंध समिति अधिकतम अवधि तक कार्य कर सकती है और समिति में किसी भी रिक्ति या रिक्तियों के कारण कार्यवाही के अमान्य होने के परिणाम 5, जो खाली रहे। प्रबंध समिति की शक्तियों को उप-कानून सं॰ 28 में निर्धारित किया गया है और उप-कानून सं॰ 28 का उप-खंड (डी) प्रबंध समिति को सदस्यों को स्वीकार करने और शेयर आवंटित करने का अधिकार देता है। उप-कानून सं॰ 36 सामान्य निकाय की शक्तियों और सामान्य निकाय को बुलाने के तरीके का वर्णन करता है। उपखंड (vi) सामान्य निकाय को किसी सदस्य के निष्कासन से निपटने का अधिकार देता है। उपनियम सं॰ 37 (बी) यह स्पष्ट करता है कि आम सभा की बैठक में समाज के सभी सदस्य शामिल होने चाहिए।

7. उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शनों को उपनियमों में रखते हुए, जब हम इसमें शामिल विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वर्ष 1982 में सोसाइटी के गठन के समय पहली बार में सोसाइटी में 28 सदस्यों की सदस्यता थी, जो 30.06.1982 पर बढ़कर 43 हो गई और धीरे-धीरे सदस्यता 31.03.1997 पर बढ़कर 75 हो गई, जब वर्ष 1996 में 37 सदस्यों को प्रवेश दिया गया था। वास्तव में, पूरा विवाद उन 37 व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में स्वीकार करने से संबंधित है, जिनकी मूल रूप से संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए धन से खरीदी गई भूमि में आवंटन प्राप्त करने की आकांक्षाओं ने आपस में इस विवादास्पद और जटिल मुकदमेबाजी के लिए गुंजाइश दी। वर्ष 1982 में सोसायटी ने थोकट्टा गाँव के सर्वेक्षण सं॰ 233 में 1 एकड़ 14 गुंटा की भूमि खरीदी। जमीन की पूरी लागत का भुगतान संस्थापक सदस्यों में से 11 ने किया था।

8. इस न्यायालय के समक्ष रखे गए बयानों में से एक में, यह खुलासा किया गया है कि 30.06.1984 पर, भूमि की लागत के लिए सदस्यों से एकत्र की गई अग्रिम राशि 1,000/- थी और योगदानकर्ताओं की संख्या 33 थी, जिनमें से दो ने कहा कि उन्होंने सोसाइटी में जमा की गई अग्रिम राशि वापस ले ली है।

9. जो भी हो, सहकारी समितियों के उप-पंजीयक ने समिति के अध्यक्ष और सचिव को संबोधित एक पत्र में श्री श्रीनिवास राव और अन्य लोगों से प्राप्त एक अभ्यावेदन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि प्रबंध समिति ने अपनी बैठक में उन्हें समिति के सदस्यों के रूप में नामांकित करने से इनकार कर दिया। यह उप-पंजीयक के कार्यालय द्वारा सहकारी उप-पंजीयक को भेजा गया था। सहकारी उप-पंजीयक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप-पंजीयक ने उक्त दिनांक 1 में सोसायटी को संकेत दिया कि श्री श्रीनिवास राव और अन्य लोगों का अनुरोध वास्तविक है और वे सोसाइटी के सदस्य बनने के योग्य हैं और इसलिए उन्हें सदस्य के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए। उनकी सदस्यता के प्रवेश की सूचना उप-पंजीयक के कार्यालय को देने का भी निर्देश दिया गया।

10. आई. डी. 2 को शाम 6 बजे हुई कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया कि आई. डी. 1 के कार्यसूची के अनुसार, 37 नए आवेदकों को सोसायटी में प्रवेश देने के मामले पर पूरी तरह से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से उन्हें सदस्यों के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, उक्त कार्यवृत्त में कहा गया है कि नए प्रवेशकों के सहयोग से, इच्छुक नए सदस्यों के लिए भूमि का एक उपयुक्त टुकड़ा खरीदा जा सकता है और 37 सदस्य या कोई अन्य सदस्य जो भूखंड साझा करना चाहते हैं, उन्हें सोसाइटी के दूसरे उद्यम के रूप में खरीदी जाने वाली भूमि में समायोजित किया जाएगा।

11. उप-पंजीयक, आवास को संबोधित 04.10.1996 दिनांकित एक पत्र द्वारा, सोसायटी ने 03.10.1996 पर आयोजित बैठक में 37 नए आवेदकों को सदस्यों के रूप में स्वीकार करने के उपरोक्त प्रस्ताव की पुष्टि की। इसके बाद, आम सभा की बैठक सोसायटी के परिसर में शाम 6 बजे आयोजित की गई थी। एजेंडा नए सदस्यों के प्रवेश की पुष्टि करना और एक नए उद्यम की संभावनाओं का पता लगाना भी था। अनुसमर्थन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी पुष्टि की गई। आम सभा की बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। यह विचार-विमर्श किया गया कि चूंकि नए सदस्य उस समय शामिल नहीं हुए थे जब भूमि खरीदी गई थी और उक्त भूमि खरीदने के लिए योगदान केवल उन 11 सदस्यों द्वारा किया गया था जो आम सभा की बैठक की तारीख को सदस्य बने रहे, इसलिए अकेले उन्हें ही उक्त भूमि में आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

12. दिनांक 1 की कार्यवाही द्वारा, आंध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 8 4 (2) के तहत एक सामान्य निर्देश सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह निर्देश भी शामिल था कि कोई भी समिति किसी भी समय भूखंडों के साथ प्रदान किए गए सदस्यों के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा को छोड़कर किसी भी नए सदस्य को सेवा में प्रतीक्षा करने के लिए स्वीकार नहीं करेगी। यह भी निर्देश दिया गया कि सोसाइटी का कोई भी सदस्य, जिसे घर या घर की जगह आवंटित नहीं की गई है, आगामी चुनावों में तब तक मतदान करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह सोसाइटी में सदस्य के रूप में एक वर्ष पूरा नहीं कर लेता। निर्वाचन अधिकारियों को समाज के सदस्यों की मतदाता सूची तैयार करते समय उक्त पहलू को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। अधिनियम की खंड 4 (2) के आधार पर, सभी सहकारी समितियों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

17.04.1997 पर जारी सामान्य निर्देश के अनुसार, उप-पंजीयक ने सोसायटी को दिनांक 01.12.1998 पर एक नए संचार के साथ आगे आए, जिसमें कहा गया कि उसके कार्यालय द्वारा अपने दिनांक 25.09.1996 पत्र में जारी किए गए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इसके बाद, 20.07.1999 दिनांकित एक संचार द्वारा, 03.10.1996 पर आयोजित बैठक में भर्ती किए गए सदस्यों को सूचित किया गया कि उनकी स्वीकृति के बाद, 16.07.1999 पर आयोजित समिति की बैठक में सभी 37 सदस्यों को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। Rs.100 का सदस्यता शुल्क भी चेक के रूप में वापस कर दिया गया था। उक्त दिनांकित 20.07.1999 पत्र में श्री के. श्रीनिवास राव द्वारा दायर 1999 की एक रिट 9 याचिका का संदर्भ दिया गया था, जिसमें उप-पंजीयक के दिनांकित 01.12.1998 के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13.07.1999 पर खारिज कर दिया गया था।

13. 1999 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 3720 में एकल न्यायाधीश के दिनांकित 13.07.1999 के आदेश के विपरीत, श्रीनिवास राव ने 1999 की एक रिट अपील सं॰ 1056 को प्राथमिकता दी। खण्ड पीठ ने उक्त रिट अपील में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

> "विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि याचिकाकर्ता निर्देशों को वापस लेने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है, बरकरार नहीं रखी जा सकती है जैसा कि सोसायटी द्वारा पारित बाद के आदेश से प्रदर्शित किया गया है, जिसे इस अपील में रिकॉर्ड पर रखा गया है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण और ऊपर की गई टिप्पणियों में, अपील विचाराधीनता रहने के दौरान पारित आदेश को दरकिनार किया जा

सकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता की सदस्यता गुण-दोष पर निर्णय लिए बिना रद्द कर दी गई थी, समिति के लिए यह खुला छोड़ दिया गया है कि वह याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता की सदस्यता के संबंध में कानून के अनुसार गुण-दोष पर निर्णय ले और उप-पंजीयक या सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किए बिना और अपीलकर्ता को सुनने के बाद। रिट अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं "

25 अन्य सदस्य जिन्हें श्री श्रीनिवास राव की तरह ही रखा गया था, उन्होंने 1999 की रिट याचिका सं॰ 18294 दायर की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 1999 की रिट अपील सं॰ 1056 में दिनांक 10 02.08.1999 के खण्ड पीठ के आदेश पर भरोसा करते हुए सोसायटी की दिनांक 20.07.1999 की कार्यवाही को दरकिनार कर दिया और उन्हें ऊपर निर्दिष्ट खण्ड पीठ के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।

14. इसके बाद, सोसायटी ने 37 सदस्यों को दिनांक आईडी2 जारी किया, जिसमें 1999 की रिट अपील में खण्ड पीठ के आदेश का संदर्भ देने के बाद आईडी4 और 1999 की रिट याचिका में आईडी1 के आदेश का उल्लेख करने के बाद सदस्यों से कारण दिखाने का आह्वान किया गया कि उन्हें क्यों नहीं निष्कासित किया जाना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में किसी भी सदस्य को प्रवेश देने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, के. शिवराम राजू और सी. विश्वम के कहने पर, 2000 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 11268 में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसने संस्थापक सदस्य होने का दावा किया था। उक्त रिट याचिका का निपटारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें 1999 की रिट अपील

2 में खण्ड पीठ के आदेश और संबंधित रिट याचिकाओं और उस रिट याचिका में दायर कुछ अन्य विविध याचिकाओं का संदर्भ दिया गया था। अंततः, विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में कहाः

> "इसमें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसाद द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि मतदाता सूची में खामियां हैं जिनके लिए मतदाता सूची को ठीक करने की आवश्यकता होती है। यह तर्क इस आधार पर दिया गया है कि 37 नए सदस्यों को निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। यह तर्क गलत है और इस अदालत द्वारा 11 बार विचार करने का आदेश नहीं देता है। रिट याचिकाकर्ताओं सहित 37 सदस्य आज तक सोसायटी के वैध सदस्य हैं जिन्हें कानून के अनुरूप जारी की गई किसी भी औपचारिक कार्यवाही द्वारा ऐसी सदस्यता से वंचित नहीं किया गया है। हालाँकि, जैसा कि यह कहा जा सकता है कि मतदाता सूची में कमियाँ एक सहकारी समिति के चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं हैं। तदनुसार तर्क को खारिज कर दिया जाता है।"

15. सहकारी समितियों के पंजीयक के कहने पर समितियों के धन के कथित दुरुपयोग के आधार पर अभियोजन शुरू करने से संबंधित एक और कार्यवाही शुरू की गई और बाद में आंध्र प्रदेश सरकार, आवास विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2004, ज्ञापन सं॰ 2768/CH1/2003-9 में एक आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश द्वारा, सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को दरकिनार करते हुए यह भी कहा कि चुनाव में भाग लेने वाले 37 विवादित सदस्यों के अमान्य मतों के समर्थन से अस्तित्व में आई मौजूदा समिति को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए

और समाज के मामलों को सही करने के लिए 37 विवादित सदस्यों को बदला जाना चाहिए।

16. 37 व्यक्तियों की सदस्यता को अमान्य घोषित करने वाले 29.03.2004 के आदेश के उक्त हिस्से को सोसायटी द्वारा 2004 की रिट याचिका सं॰ 7794 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके चुनौती दी गई थी। दिनांक 2 के आदेश द्वारा, विद्वत एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश की पुष्टि करते हुए, जहां तक कि उसने दिनांक 3 और 4 की कार्यवाहियों को दरकिनार कर दिया है, हालांकि, यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, जहां तक यह मौजूदा समिति के सदस्यों के चुनाव और 11 सदस्यों को भूखंडों के आवंटन से संबंधित है, को गैर-कानूनी माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम प्रतिवादी ने उस प्रश्न में प्रवेश किया है जिसका उसके समक्ष प्रचार नहीं किया गया था।

17. 1999 की रिट अपील सं॰ 1056 और 1999 की रिट याचिका सं॰ 18294 में पारित आदेश के अनुसरण में, संभागीय सहकारी अधिकारी ने अपने दिनांक 02.04.2004 के आदेश द्वारा, उप-मंडल सहकारी अधिकारी, सिकंदराबाद मंडल को सदस्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सोसायटी की आम सभा बुलाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया। संभागीय सहकारी अधिकारी ने 22.12.2004 पर आगे का आदेश पारित किया और उप-मंडल सहकारी अधिकारी, सिकंदराबाद मंडल को, 1999 की रिट अपील सं॰ 1056 में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में सदस्यता तय करने के लिए सामान्य निकाय की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत करने के लिए आगे के निर्देश दिए। उक्त निर्देश पूर्वाहन अनुसार, आम सभा की बैठक की तारीख और समय 22.05.2005 पर 11.30 सुबह तय किया गया था। हालांकि, जैसा कि निर्धारित किया गया था, सदस्यों ने कहा कि वे 22.05.2005 पर एकत्र हुए थे, पीठासीन अधिकारी ने बैठक शुरू नहीं की। इसलिए, उप-मंडल सहकारी अधिकारी के निर्देश के अनुसार बैठक

13 नहीं हुई। फिर भी, 15 सदस्यों ने कहा कि वे बैठक के साथ आगे बढ़े और 37 सदस्यों के हित के प्रतिकूल कुछ प्रस्ताव पारित किए और इसे सहकारी समिति के अधिकारियों को भेज दिया। लेकिन, सहकारी समिति के उप-पंजीयक ने समिति को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्य निकाय की बैठक बुलाने के मुद्दे की उप-पंजीयक द्वारा फिर से जांच की गई और 2000 की रिट याचिका सं॰ 11268 में 08.11.2000 के आदेश और 2004 की रिट याचिका सं॰ 7794 में 26.04.2004 के अंतरिम आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि 22.05.2005 पर प्रस्तावित आम निकाय की बैठक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उक्त पत्राचार से यह भी पता चला कि उप-मंडल सहकारी अधिकारी, जिन्होंने आम सभा की बैठक बुलाई थी, ने 22.05.2005 पर सदस्यों को उक्त स्थिति के बारे में बताया कि कार्यसूची पर कोई चर्चा नहीं होगी और आम सभा की बैठक नहीं होगी। अंततः 15 सदस्यों द्वारा पारित किए जाने का दावा किए गए तथाकथित प्रस्ताव को अमान्य माना गया।

18. 2003 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 701 में भी रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें 2000 के सी. टी. ए. सं॰ 160 में आंध्र प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित 1998 के ए. आर. सी. 3 दिनांक 10.03.2002 के एक पुरस्कार को रद्द कर दिया था। उक्त रिट याचिका न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दी गई। 14 न्यायाधिकरण के आदेश का योग और सार यह था कि पदोन्नति करने वाले सदस्यों को भूमि का तथाकथित आवंटन, लेआउट की मंजूरी का अनुमान लगाना वैध नहीं था और इसलिए, सोसाइटी द्वारा संस्थापक सदस्यों को भूखंड आवंटित करने का प्रस्ताव, लेआउट की मंजूरी के अधीन, मनमाना और अवैध माना गया था। तथाकथित संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि उक्त आदेश भूखंडों के आवंटन से संबंधित उपनियमों के अनुसार उनकी वरिष्ठता को

ध्यान में रखते हुए लेआउट को मंजूरी देने के बाद सोसायटी के सदस्यों के पक्ष में भूखंडों के आवंटन पर विचार करने से सामान्य निकाय को नहीं रोकेगा।

19. सोसायटी के उदय के बाद और इसके पंजीकरण के बाद हुए विकास के साथ-साथ सोसाइटी में नए सदस्यों के प्रवेश से संबंधित मुद्दे और सोसाइटी के विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर ध्यान दें के बाद, इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों की शुद्धता की जांच करने से पहले, मूल सदस्यों और उन सदस्यों के अधिकारों का पता लगाने के लिए उपनियमों के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो बाद में सोसाइटी में भर्ती होने का दावा करते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समाज का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के लिए आवास सुविधा प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को उप-कानून संख्या 2 में संक्षेप में बताया गया है। 15 जहाँ तक सदस्यता का संबंध है, पात्रता उप-कानून संख्या 5 में निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार हैः

"सदस्यता योग्यताः

5. कोई भी व्यक्ति जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया है; और जो अनुबंधित और स्वस्थ दिमाग का है और जिसके नाम पर या अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम पर शहर में कोई घर नहीं है और जो उसी क्षेत्र में किसी अन्य गृह निर्माण समिति का सदस्य नहीं है, वह सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र होगा, नाबालिग को उनके कानूनी अभिभावकों द्वारा से सहयोगी सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन वे वोट देने के पात्र नहीं होंगे या लाभ में कोई रुचि नहीं रखेंगे।"

20. उप-कानून संख्या 5 के पढ़ने से पता चलता है कि सदस्य बनने के योग्य होने के आदेश, एक व्यक्ति को वयस्क होना चाहिए, उसे स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, उसके नाम पर या उसकी पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम पर शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए और वह उसी क्षेत्र में किसी अन्य गृह निर्माण समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वह सदस्य बनने का पात्र होगा।

21. हालांकि, उपनियमों में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति वोल्टास कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि सोसायटी का गठन वोल्टास के कर्मचारियों द्वारा किया गया था और नाम ही यह स्पष्ट करता है कि सोसाइटी का गठन वोल्टास के कर्मचारियों द्वारा आवास सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था, यह अनिवार्य है कि व्यक्ति वोल्टास का कर्मचारी होना चाहिए। उप-कानून संख्या 6 के साथ पठित उप-कानून संख्या 16 संख्या 4 के अनुसार, जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है, उसे शेयरधारक होना चाहिए और इस तरह के हिस्से की लागत 5000 शेयरों से बनी Rs.100 तय की गई है, जो समाज की राजधानी बनाएगी। जब शेयर के आवंटन के लिए सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सोसायटी के सचिव को किया जाता है, तो ऐसे आवेदन का निपटान प्रबंध समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे प्रवेश देने और शेयर आवंटित करने या विवेक को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। शेयर आवंटित करने से इनकार करने की स्थिति में, कारणों को जोड़ना होगा। उप-कानून संख्या 6 (बी) में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा कोई निर्णय नहीं सूचित किया जाता है, तो सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख से 50 दिनों के भीतर, सोसायटी को आवेदन की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति की तारीख पर ऐसे आवेदक को सदस्य के रूप में भर्ती किया हुआ माना जाएगा और सचिव को इस तरह के प्रवेश को प्रभावी बनाना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति को

उप-कानून संख्या 7 के आधार पर समाज के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाता है, तो वह समाज की सेवाओं के लिए पात्र होगा।

22. सोसायटी में किसी व्यक्ति की सदस्यता की पुष्टि होने के बाद, सोसाइटी से उसका बाहर निकलना या तो अयोग्यता के माध्यम से हो सकता है जैसा कि उपनियम संख्या 8 के तहत प्रदान किया गया है, या उपनियम सं॰ 12 के तहत शेयर पूंजी की निकासी के माध्यम से या उपनियम सं॰ 16 के तहत निष्कासन के माध्यम से हो सकता है। यदि सदस्यता से बाहर निकलना अयोग्यता के रूप में है, तो यह उप-कानून संख्या 8 के उप-खंड (i) से (iv) में से किसी एक के तहत आना चाहिए। यदि यह शेयर पूंजी की निकासी के 17 तरीके से है, जैसा कि उपनियम सं॰ 12 के तहत प्रदान किया गया है, तो फिर से उक्त उपनियम में निहित शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी सदस्य को निष्कासित किया जाना है, तो उप-कानून सं॰ 16 (1) के तहत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उप-कानून सं॰ 16 (1) के तहत निर्धारित निष्कासन के लिए कोई प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में, ऐसे निष्कासन को उप-कानून सं॰ 16 (2) के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक की मंजूरी होनी चाहिए। इसलिए, किसी सदस्य के निष्कासन का दावा केवल समाज द्वारा लिए गए रुख से नहीं किया जा सकता है। सहकारी समिति के पंजीयक के अनुमोदन का आदेश होना चाहिए जो उपनियम सं॰ 16 (1) के तहत निषिद्ध निष्कासन की पुष्टि करता है या अन्यथा, समिति द्वारा दावा की गई सदस्यता का ऐसा निष्कासन वैध नहीं हो सकता है।

23. उप-कानून में ध्यान देने योग्य एक अन्य प्रावधान प्रबंध समिति का कार्यकाल है, जिसे उप-कानून सं॰ 22 के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा और समिति की किसी भी रिक्ति या रिक्तियों के कारण प्रबंध समिति की किसी भी कार्यवाही को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, जो खाली रह सकती है। उक्त उप-कानून के तहत, यह निर्धारित किया गया है

कि समिति के सभी सदस्य समिति के पद की अवधि समाप्त होने पर अपना पद खाली कर देंगे। ये सभी उपनियमों की मुख्य विशेषताएं हैं। उपरोक्त विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, उप-कानून सं॰ 36 के तहत, यह कहा गया है कि समाज के 18 प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में अंतिम प्राधिकरण, सामान्य निकाय में निहित होगा। यहाँ तक कि किसी सदस्य का निष्कासन भी केवल सामान्य निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट शक्तियों में से एक है।

24. उप-कानून में उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए, जब हम समाज के उद्भव और उसके बाद की घटनाओं की जांच करते हैं, तो यह विवाद में नहीं है कि समाज के गठन के समय, संस्थापक सदस्यों की संख्या वर्ष 1981 में 28 थी। वर्ष 1981-82 के बाद से सदस्यों की एक सूची से पता चलता है कि 30.06.1982 पर सदस्यता बढ़कर 43 हो गई, जो स्थिर रही, हालांकि वर्ष 1988 में किसी समय सदस्यता में मामूली वृद्धि होकर 56 हो गई थी। 31.03.1997 तक, सदस्यों की कुल संख्या 75 थी। जो भी हो, जब सोसायटी ने वर्ष 1982 में थोकट्टा गाँव के सर्वेक्षण में 1 एकड़ 14 गुंटा की भूमि खरीदी, तो यह कहा गया कि भूमि की लागत सोसाइटी के 11 सदस्यों, एम. बालकृष्णन, के. शिवराम राजू, वी. शिवरामकृष्ण, पी. एस. शास्त्री, एन. सूर्यप्रकाश राव, के. भक्तवत्सलम, टी. एस. बनर्जी, टी. एन. शंकर, सी. विश्वम, यू. तलपति और के. जी. के. मूर्ति द्वारा वहन की गई थी। एक अन्य बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1983-84 में अन्य सदस्यों से भूमि की लागत एकत्र की गई थी, जिसके अनुसार कुल निवेश Rs.64,000/- के योग में था।

25. जबकि 19 सोसायटी द्वारा भूमि की खरीद की गई थी और आवास सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया की जांच की जा रही थी और वर्ष 1996 तक लंबित थी, सोसाइटी के सदस्यों के रूप में 37 व्यक्तियों के प्रवेश से संबंधित मुद्दा सामने आया। इसलिए, इस बारे में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि थोकट्टा गांव

में पहले से खरीदी गई 1 एकड़ और 14 गुंटा भूमि के संबंध में आवास सुविधा से कैसे निपटा जाए, हमें सोसायटी की सदस्यता से बचना होगा, विशेष रूप से उन 37 व्यक्तियों के दावे के बारे में जो सोसाइटी के सदस्य बन गए हैं, जो आवास के रूप में वितरण के लिए सोसाइटी द्वारा पहले से खरीदी गई भूमि में अपने हिस्से का दावा भी करते हैं।

26. जहाँ तक 37 सदस्यों के उक्त दावे का संबंध है, पहला दस्तावेज सहकारी समिति के उप-पंजीयक का दिनांकित पत्र है, जो उस समिति को संबोधित है जिसके द्वारा समिति से उन्हें सदस्यों के रूप में स्वीकार करने और उप-पंजीयक को सूचित करने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र के अनुसार, सोसायटी की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.10.1996 के कार्यवृत्त से पता चलता है कि दिनांकित 18.09.1996 के अनुसार, 37 आवेदकों के प्रवेश से संबंधित मामले पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी और सर्वसम्मति से उन्हें सदस्यों के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था। हालाँकि, उक्त बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि पहले से खरीदी गई भूमि में हिस्सेदारी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के दावे पर एक अलग उद्यम में विचार किया जाएगा। उन 37 सदस्यों के प्रवेश की पुष्टि करते हुए, सोसायटी द्वारा 04.10.1996 पर उप-पंजीयक को एक 20 पत्र भी भेजा गया था। इसके अलावा, आई. डी. 1 पर एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि सोसायटी में 37 सदस्यों के प्रवेश की भी आम सभा द्वारा पुष्टि की गई थी, हालांकि थोकट्टा गांव में खरीदी गई भूमि के संबंध में उनके दावे को आम सभा में स्वीकार नहीं किया गया था।

27. उपरोक्त कार्यवाहियों से, यह कहा जाना चाहिए कि सोसायटी में 37 सदस्यों का प्रवेश सामान्य निकाय की तारीख के अनुसार एक निष्कर्षित मुद्दा था, अर्थात् 04.04.1997। हालाँकि, सहकारी विभाग के कार्यालयों ने वर्ष 1998 में अचानक यू-टर्न

ले लिया, जब उप-पंजीयक ने सोसायटी को 01.12.1998 पर एक संचार जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उसके द्वारा अपने दिनांकित 25.09.1996 पत्र में जारी किए गए निर्देशों को सहकारी समितियों के पंजीयक की कार्यवाही के आधार पर वापस लिया जाना था। यह बताना होगा कि उप-पंजीयक सहकारी समितियों का उक्त रुख कानून में स्वीकार्य नहीं है और हमें किसी भी सांविधिक प्रावधान या किसी अन्य नियम या विनियमन के आधार पर इस तरह के रुख के लिए कोई समर्थन नहीं मिलता है। इसके अलावा, जब उक्त संचार दिनांक 01.12.1998 के आधार पर सोसायटी 37 व्यक्तियों की सदस्यता वापस लेना चाहती थी, तो यह मुद्दा 1999 की रिट याचिका सं॰ 3720 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष गया, जिसे 1999 की रिट अपील सं॰ 1056 में विद्वान सिंह न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, सदस्यता वापस लेने वाली सोसाइटी की कार्यवाही को इस टिप्पणी के साथ अलग कर दिया गया था कि 37 सदस्यों में से किसी एक की सदस्यता के संबंध में किसी न किसी तरह से निर्णय लेने के लिए सोसाइटी के लिए यह खुला है। 37 सदस्यों में से 25 अन्य व्यक्तियों के संबंध में उक्त निष्कर्ष का पालन किया गया था जब 1999 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 18294 में उनकी रिट याचिका का निर्णय दिनांक 01.09.1999 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें 1999 के रिट अपील सं॰ 1056 में निष्कर्ष का पालन किया गया था।

28. हालाँकि, सोसायटी 06.10.1999 पर कारण बताएँ नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू करना चाहती थी, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त कारण बताएँ नोटिस का पालन नहीं किया गया था। दूसरी ओर, 2011 की रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने वस्तुतः घोषणा की कि रिट याचिकाकर्ताओं सहित 37 सदस्य, आदेश की तारीख तक वैध सदस्य बन गए थे क्योंकि सोसायटी ने कानून के अनुरूप किसी भी औपचारिक कार्यवाही में ऐसी सदस्यता से वंचित नहीं किया था। उक्त आदेश में कहा गया था कि मतदाता सूची में कोई भी कथित कमियां एक सहकारी समिति के चुनाव की

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक प्रासंगिक आधार नहीं हो सकती हैं और इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि 37 नए सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2011 के डबल्यू. पी. सं॰ 11268 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश में किसी भी बाद की कार्यवाही में किसी भी समय बदलाव नहीं किया गया था, या तो अपील में या सोसाइटी द्वारा पारित किसी अन्य वैध आदेश द्वारा। वास्तव में, 22 बाद में, कथित गबन के लिए सदस्यों के अभियोजन से संबंधित एक मुद्दे पर विचार करते हुए जब राज्य सरकार ने 29.03.2004 पर एक आदेश पारित किया, तो यह निर्दोष रूप से कहा गया कि 37 व्यक्तियों की विवादित सदस्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी सदस्यता वैध नहीं थी। उक्त आदेश को 2004 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 7794 में एक अलग रिट याचिका में चुनौती दी गई थी और आदेश के उक्त हिस्से को भी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.12.2006 आदेश में दरकिनार कर दिया गया था। यहाँ फिर से यह कहा जाना चाहिए कि 2004 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 7794 में उक्त आदेश अंतिम और निर्णायक हो गया है क्योंकि इसे कानून द्वारा ज्ञात तरीके से चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त रिट याचिका सोसायटी द्वारा ही दायर की गई थी। शुद्ध परिणाम यह हुआ कि 2000 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 11268 दिनांक 18.11.2000 में पारित आदेशों और 2004 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 7794 में दिनांकित 15.12.2006 आदेश के आधार पर, इन 37 व्यक्तियों की सदस्यता की वैधता विवाद के दायरे से परे थी।

29. एक अन्य बात जिस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि देर से विभाग द्वारा इन 37 व्यक्तियों की सदस्यता की वैधता से निपटने के लिए अपने एक अधिकारी, अर्थात् उप-मंडल सहकारी अधिकारी को सोसायटी की आम सभा बुलाने और सदस्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश देकर एक प्रयास किया गया था। उक्त कार्यवाही के अनुसार, हालांकि उक्त अधिकारी द्वारा एक आम सभा की बैठक बुलाई

गई थी और एक तारीख भी 22.05.2005 के रूप में तय की गई थी, उक्त बैठक नहीं बुलाई गई थी, 23 क्योंकि उप-पंजीयक की कार्यवाही दिनांक 04.06.2005 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उप-मंडल सहकारी अधिकारी जिन्होंने आम सभा की बैठक बुलाई थी, ने सदस्यों को 22.05.2005 पर समझाया और स्पष्ट किया कि एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं होगी, अर्थात्, 37 सदस्यों के प्रवेश की वैधता के बारे में और यह कि कोई आम सभा की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं था। इसलिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, दिनांक 1 की बैठक के आधार पर 37 सदस्यों का प्रवेश अब विवाद में नहीं रह सकता है क्योंकि यह एक निष्कर्षित मुद्दा था।

30. ऐसा करते समय भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि 37 व्यक्तियों की सदस्यता को रद्द किया जाना था, तो यह उप-कानून में किसी भी प्रासंगिक प्रावधान को लागू करके किया जा सकता था, अर्थात् उप-कानून संख्या 5 के तहत प्रदान की गई पात्रता के आधार पर या उप-कानून संख्या 8 के तहत प्रदान की गई अयोग्यता के माध्यम से या उप-कानून सं॰ 12 के तहत प्रदान की गई शेयर पूंजी को वापस लेकर या उप-कानून सं॰ 16 में निर्धारित निष्कासन के माध्यम से। जहां तक पात्रता मानदंडों का संबंध है, हमारे समक्ष यह नहीं बताया गया था कि 37 सदस्यों में से किसी में भी ऐसी पात्रता की कमी है जैसा कि उपनियम संख्या 5 में निर्धारित किया गया है। हमारे सामने किसी भी स्वीकार्य सामग्री के रूप में यह भी नहीं बताया गया था कि 37 सदस्यों में से किसी को भी अयोग्यता का सामना करना पड़ा जैसा कि उपनियम संख्या 8 के तहत प्रदान किया गया था। जहां तक उप-कानून सं॰ 12 के आवेदन का संबंध है, यह कहा जाना चाहिए कि 37 सदस्यों में से 10 ने अपनी शेयर पूंजी का 24 प्रतिशत धनवापसी स्वीकार कर लिया है और आज तक 37 में से केवल 27 ही बचे हैं, जिन्होंने वर्ष 1999 के दौरान सोसायटी द्वारा जारी किए गए चेक को दिनांकित 20.07.1999 की कार्यवाही के साथ वापस कर दिया है।

31. जब हम सदस्यता के निष्कासन की बात करते हैं, तो यह सोसायटी या किसी भी प्रतिद्वंद्वी दावेदार का मामला नहीं है कि उप-कानून सं॰ 16 के तहत निर्धारित इस तरह के निष्कासन के लिए कोई कार्यवाही की गई थी और इस तरह की कार्यवाही को पंजीयक द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, नए जोड़े गए सदस्यों के निष्कासन से संबंधित पंजीयक द्वारा अनुमोदन के ऐसे किसी वैध आदेश की अनुपस्थिति में में, शेष 27 सदस्यों के सोसायटी के सदस्य नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है।

32. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, 37 सदस्यों से संबंधित, अब 27, एकमात्र अन्य प्रश्न जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह है थोकट्टा गाँव के सर्वेक्षण संख्या 233 में 1 एकड़ 14 गुंटा की भूमि में आवास के लिए सोसायटी के सदस्यों की पात्रता। जब हम उक्त मुद्दे पर विचार करते हैं, तो तथाकथित 11 संस्थापक सदस्यों का दावा है कि भूमि का पूरा मूल्य उनके द्वारा वहन किया गया था और इसलिए, वे विशेष रूप से आपस में भूमि के वितरण के हकदार हैं। इस तरह के दावे का उल्लेख 04.04.1997 पर आयोजित सोसायटी की आम सभा की बैठक में स्पष्ट रूप से किया गया था। वास्तव में, उक्त मुद्दे से संबंधित उक्त बैठक में 25 में एक गंभीर विचार-विमर्श और चर्चा हुई और आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया हैः

> "यह समझाया गया कि चूंकि नए सदस्य उद्यम में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए तत्कालीन मौजूदा 11 सदस्यों, जिन्होंने उद्यम में बने रहने का फैसला किया है, ने उन सदस्यों को राशि वापस करने के लिए सभी अतिरिक्त राशियों का योगदान दिया, जिन्होंने अपनी मर्जी से भूमि अग्रिम से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार निम्नलिखित 11 (ग्यारह) 1.वी. शिवराम कृष्ण 2.एम. बालकृष्णन 3.के. शिवराम राजू 4.पी. एस. शास्त्री 5.के. भक्तवत्सलम 6.एन. सूर्यप्रकाश राव 7.टी.

एन. शंकर 8.टी. एस. बनर्जी 9.सी. विश्वम 10.यू. तलपति 11.के. जी. के. मूर्ति एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिनके पास थोकट्टा गाँव के एस. सं॰ 233 में मौजूदा भूमि उद्यम का अधिकार है और मौजूदा उद्यम में इतने वर्षों के अंतराल के बाद किसी और सदस्य को प्रवेश देना संभव नहीं है। हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि इच्छुक सदस्य किसी भी नए उद्यम की संभावना का पता लगा सकते हैं और इसके लिए सभी सहायता दी जाएगी।"

33. हालांकि, इस तरह का रुख अध्यक्ष द्वारा आम सभा की बैठक में व्यक्त किया गया था, लेकिन आम सभा की बैठक में इस आशय का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला था। तथाकथित 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा किए गए इस तरह के दावे के अलावा, यह कहा जाना चाहिए कि इस तरह के दावे का परीक्षण उपनियमों में निहित प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, जब हम उप-कानूनों के प्रावधानों की जांच करते हैं, तो उप-कानून संख्या 2 के खंड 26 में कहा गया है कि समाज का उद्देश्य अपने सदस्यों के लाभ के लिए, नए आवासों के निर्माण के लिए सदस्यों को ऋण देने के अलावा, सहकारी सिद्धांतों के अनुसार भूमि निर्माण और खरीद, बिक्री, किराए पर लेने, पट्टे पर देने और विकसित करने का व्यापार करना है। इसलिए, इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि यह सदस्यों के लाभ के लिए है और यह सहकारी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। उप-कानून संख्या 4 प्रत्येक के 5000 शेयरों तक की कुल शेयर पूंजी निर्धारित करता है, धन का दूसरा स्रोत उप-कानून सं॰ 17 में निर्धारित किया जा सकता है। 'फंड्स' शीर्षक के तहत उप-कानून सं॰ 17 में कहा गया है कि सोसायटी आम तौर पर 10 स्रोतों से धन प्राप्त करेगी, अर्थात् सदस्यों से शेयर पूंजी, सरकार से ऋण, सदस्यों से जमा, प्रवेश और अन्य शुल्क, एपी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड, अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंक, बीडीए, एलआईसी, हैडको

और वोल्टास लिमिटेड। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या किसी अन्य स्रोत से कोई निधि एकत्र की गई थी, सिवाय सदस्यों से शेयर पूंजी और उन सदस्यों द्वारा निवेश की गई धनराशि के जिन्होंने शुरू में सोसायटी का गठन किया था और उन सदस्यों द्वारा जो बाद में सोसाइटी में शामिल हुए थे। वास्तव में, इस न्यायालय के दिनांकित 04.09.2012 के आदेश में एक प्रश्न के निर्देश के अनुसार, जिसका जवाब पंजीयक द्वारा दिए जाने का निर्देश दिया गया था, यह पता चला है कि बिक्री विलेख के लिए योगदान Rs.48,000/- था, हालांकि नकद पुस्तिका के अनुसार भुगतान किया गया प्रतिफल 27 रुपये. 2,60,000-के रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा, संलग्नक 2 के माध्यम से एक अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ एक सूची संलग्न की गई थी, जिसमें खुलासा किया गया है कि समाज के 34 सदस्यों द्वारा 24.08.1982 और 30.04.1982 के बीच अलग-अलग तिथियों पर रु. 3,06,795 की राशि का योगदान किया गया था।

34. इस न्यायालय द्वारा संलग्नक 4 के माध्यम से किए गए एक अन्य प्रश्न के लिए, यह खुलासा किया गया है कि 30.04.1982 के बाद, यानी 11.10.1982 और 30.11.1989 के बीच, Rs.5000 से Rs.39,000/- तक की विभिन्न राशियों में योगदान किया गया था, हालांकि कई सदस्यों को धनवापसी के माध्यम से अपने निवेश वापस मिल गए, जबकि कुछ सदस्य ऐसे निवेशों को बनाए रखना जारी रखते हैं। संलग्नक 6 के माध्यम से एक अन्य प्रश्न के लिए, पंजीयक ने खुलासा किया है कि 25.09.1996 के बाद ऐसी सदस्यता की मांग करने वाले 34 सदस्यों ने Rs.1500 से लेकर रु. 2,40,000 तक की राशि का निवेश किया है, जो कुल मिलाकर Rs.17,48,569/- है। उक्त राशि के लिए व्यय के विभाजन का भी संलग्नक में खुलासा किया गया है। यह सवाल कि क्या इस तरह के निवेश और किए गए खर्चों की जांच की जानी चाहिए और सोसाइटी द्वारा किए गए ऐसे खर्चों की सत्यता को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं,

यह तथ्य सामने आता है कि संस्थापक सदस्यों के साथ-साथ जिन्हें बाद में सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया था, उन्होंने सोसाइटी में जमा के रूप में बड़ी राशि का निवेश किया है। इसलिए, विचार करने के लिए सवाल यह है कि उन राशियों को समाज के कोष में लाने के बाद उनका इलाज कैसे किया जाए।

35. इस संदर्भ में, उपनियम सं॰ 17 महत्वपूर्ण है। यह बताना होगा कि सोसाइटी के सदस्यों का सोसाइटी के खातों में विभिन्न जमा करते समय जो भी इरादा हो, क्योंकि सोसाइटी के सदस्यों द्वारा निवेश की गई राशि को सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जा सकता है, या तो शेयर पूंजी के लिए हो सकती है, जो प्रत्येक Rs.100 के 5000 शेयरों से अधिक नहीं हो सकती है या सदस्यों द्वारा जमा के रूप में हो सकती है जैसा कि उप-कानून सं॰ 17 के तहत प्रदान किया गया है। चूंकि, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित शेयरों के आधार पर सदस्यता की पुष्टि की गई है, इसलिए सोसाइटी के खातों में जो भी अन्य राशि लाई जाती है, उसे केवल सदस्यों की जमा राशि के रूप में लिया जा सकता है। इसलिए, सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग केवल थोकट्टा गांव के सर्वेक्षण में मूल रूप से खरीदी गई लगभग 1 एकड़ और 14 गुंटा भूमि की लागत को पूरा करने के लिए या किसी अन्य भूमि में भविष्य में किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए किया जा सकता है जिसे खरीदा जाना है या सदस्यों द्वारा भवन निर्माण के उद्देश्य से किसी भी ऋण को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत सदस्य यह दावा नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि सर्वेक्षण में भूमि की खरीद उनके द्वारा सोसायटी को दी गई राशि से और उसमें से की गई थी, इसलिए इस तरह से खरीदी गई भूमि विशेष रूप से उन सदस्यों की होनी चाहिए। अलग-अलग सदस्यों के ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इस तरह का दावा सहकारी सिद्धांतों के विपरीत होगा, जो समाज का उद्देश्य है जब इसका गठन किया गया था।

36. एक बार जब सोसायटी द्वारा थोकट्टा गाँव में 1 एकड़ और 14 गुंटा की सीमा में सर्वेक्षण में भूमि खरीदी जाती है, तो संपत्ति सोसाइटी में निहित हो जाती है। इसलिए, यह समाज को इस बात पर विचार करना है कि सहकारी सिद्धांतों और उन उद्देश्यों के अनुसार उक्त भूमि से कैसे निपटा जाए जिनके साथ समाज का गठन किया गया था जैसा कि उपनियमों में उल्लेख किया गया है। यह व्यक्तिगत सदस्यों का दावा नहीं है कि भूमि को उसके सदस्यों के बीच वितरण के उद्देश्य से किस तरह से निपटाया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति के जोखिम पर, यह कहना होगा कि जिन सदस्यों ने सोसायटी में अपने धन का योगदान दिया है, उन्हें इस आधार पर संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि उन्होंने भूमि की खरीद के लिए निवेश किया था। इसलिए संस्थापक सदस्यों और बाद में समाज में भर्ती होने वाले सदस्यों दोनों के उक्त दावे को खारिज कर दिया जाता है।

37. इसलिए, स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में कहें तो, संस्थापक सदस्यों या बाद के सदस्यों द्वारा किए गए उन सभी निवेशों को, जो शेयर पूंजी से संबंधित हैं, केवल उनकी जमा राशि के रूप में लिया जा सकता है जो समाज की निधियों का हिस्सा हैं। इसलिए, सोसाइटी सदस्यों द्वारा संबंधित तिथियों से की गई ऐसी जमाओं के लिए लेखा देने के लिए बाध्य है और बाजार में जो भी प्रचलित ब्याज ऐसी जमाओं पर जमा होना चाहिए और सदस्य की इच्छा के आधार पर, यह सोसाइटी को निर्णय लेना है कि या तो एक निश्चित अवधि के बाद इस तरह से जमा की गई राशि की वापसी के लिए या अपने विभिन्न सदस्यों को अंतिम वितरण की स्थिति में भूमि की लागत को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। 38.इस संदर्भ में, 2003 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 701 में पारित दिनांक 14.12.2006 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

"यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रस्ताव को एक अनुमोदित लेआउट के बिना पारित किया गया था, जैसा कि उपनियमों के तहत आवश्यक है। यदि ऐसा है, तो बैठक बुलाने और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कुछ भूखंड आवंटित करने का प्रस्ताव पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्ताव पारित करने के लिए कोई वैध समिति थी या नहीं। इसलिए, मेरी सुविचारित राय है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले विवादित आदेशों को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। रिट याचिका गुणदोष से रहित है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, यह आदेश सामान्य निकाय को भूखंडों के आवंटन से संबंधित उपनियमों के अनुसार उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सोसायटी के सदस्यों के पक्ष में भूखंडों के आवंटन पर विचार करने से नहीं रोकेगा। (रेखांकित करना हमारा है)"

39. हम पाते हैं कि 2003 की रिट याचिका सं॰ 701 में उक्त आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया ऐसा निष्कर्ष और निर्देश न केवल एकमात्र मार्ग है, बल्कि समाज द्वारा पालन किया जाने वाला उपयुक्त मार्ग भी है। हमारे सुविचारित विचार में, समाज द्वारा पहले से खरीदी गई भूमि से निपटने का कोई भी अन्य प्रयास न केवल सहकारी सिद्धांतों के विपरीत होगा, बल्कि केवल और जटिलताएं पैदा करेगा और इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से अराजकता और भ्रम पैदा होगा। इसलिए, न तो संस्थापक सदस्य और न ही जिन्हें बाद में सदस्यों के रूप में शामिल/भर्ती किया गया था, वे

किसी विशेष तरीके से किसी भी वरीयता या आवंटन के अधिकार का दावा कर सकते हैं, सिवाय उस तरीके के जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने उक्त आदेश में निर्देश दिया है।

40. उपरोक्त पैराग्राफ में जो पाया गया है, उससे हम अंततः निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) इस समापन पैराग्राफ में हमारे अन्य निर्देशों का पालन आदेशने के लिए, सबसे पहले, हम आंध्र प्रदेश की सहकारी समितियों के पंजीयक को निर्देश देते हैं कि वे उप-मंडल सहकारी अधिकारी के पद पर अपने एक जिम्मेदार अधिकारी को सोसायटी के अभिलेखों से उसके द्वारा निर्धारित सभी सदस्यों की एक आम निकाय बैठक बुलाने और सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव आदेशने के लिए नियुक्त आदेशें। पंजीयक द्वारा नामित ऐसे अधिकारी को प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से आम निकाय की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए, चुनाव आयोजित करना चाहिए और ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करना चाहिए और इसे पंजीयक को रिपोर्ट करना चाहिए जो इसे समाज में प्रकाशित करेगा ताकि प्रबंध समिति समाज का नियंत्रण ले सके। इसके बाद ऐसा नामित अधिकारी अपने अन्य पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, सचिव आदि के चुनाव के लिए प्रबंध समिति का मार्गदर्शन करेगा और संबंधित पद के लिए उनके सफल चुनाव के बाद, आधिकारिक तौर पर सोसायटी का प्रबंधन इस प्रकार चुने गए सचिव को सौंप देगा। उपरोक्त कवायद इस आदेश के संचारण की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीयक द्वारा की जाएगी। उक्त अभ्यास के पूरा होने के बाद, इस न्यायालय में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इस निर्देश के सफल अनुपालन के बाद, उपखंड (ii) से (xi) में निहित शेष निर्देशों का समाज के उपनियमों के अनुसार सफलतापूर्वक निर्वाचित पदाधिकारी और प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा पालन और निष्पादन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड में निहित

निर्देश का पालन करते समय, पंजीयक द्वारा नामित अधिकारी को गणना करने का पूरा अधिकार होगा। सोसायटी के सदस्य, आम सभा की बैठक की तारीख निर्धारित करते हैं, प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आम सभा में चुनाव आयोजित करते हैं, उसके बाद प्रबंध समिति को पदाधिकारी, अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी का चुनाव करने और परिणाम घोषित करने में सक्षम बनाते हैं। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यह निर्देश सभी संबंधित लोगों पर लागू होगा। इस निर्देश का पालन करने के बाद ही पंजीयक अनुपालन के एक महीने के भीतर इस न्यायालय की पंजीकरण में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसके बाद, यदि इस पहलू पर कोई और निर्देश जारी किए जाने हैं, तो इस न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

(ii) जो समाज 29.10.1982 से उभरा है, उसे संस्थापक सदस्य के रूप में या बाद में प्राप्त सदस्यता के रूप में किसी के दावे के बावजूद स्थायी रूप से अस्तित्व में रहना होगा और इस तरह, किसी भी अधिमानी अधिकार का दावा करना होगा।

(iii) चूंकि समाज का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार समाज के सदस्यों को आवास सुविधाएं प्रदान करना है, इसलिए इस तरह का अधिकार समाज के उपनियमों के अनुसार सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(iv) 37 सदस्यों का यह अधिकार कि उन्हें समिति के संकल्प दिनांक 1 द्वारा समाज में प्रवेश दिया गया है, एक निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों द्वारा की गई है, जो अब अंतिम और आत्यन्तिक हो गया है।

(v) यद्यपि 37 सदस्यों का प्रवेश अंतिम और निर्णायक हो गया है, लेकिन जिन सदस्यों ने अपनी 34 जमा राशि स्वीकार कर ली है, दोनों शेयर पूंजी या किसी अन्य राशि के लिए, जिसे सोसायटी द्वारा उन्हें दिनांकित 20.07.1999 के नोटिस के साथ

भेजा गया था, वे सोसाइटी के सदस्य नहीं रह गए। नतीजतन, स्वीकार किए गए 37 सदस्यों में से केवल 27 सदस्य बने हुए हैं।

(vi) इसी तरह, जिन संस्थापक सदस्यों की संख्या 28 बताई गई थी, आज की तारीख में, शेष 11 सदस्यों के दावे को स्वीकार करते हुए, जिन्होंने कहा कि समाज में जमा राशि के माध्यम से और अधिक राशि का निवेश किया है ताकि समाज अन्य संस्थापक सदस्यों के दावों का निपटान कर सके, वे समाज के सदस्य नहीं रह गए। इस प्रकार, संस्थापक सदस्यों में, केवल 11 सदस्य बने हुए हैं जिनके नाम पैराग्राफ 24 में उल्लिखित किए गए हैं।

(vii) थोकट्टा गाँव के सर्वेक्षण में 1 एकड़ और 14 गुंटा तक की भूमि की खरीद सोसायटी की है और यह सोसाइटी का काम है कि वह उक्त भूमि के वितरण को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से देखे।

(viii) जहां तक वितरण का संबंध है, जैसा कि 2003 के डब्ल्यू. पी. सं॰ 701 दिनांक 14.12.2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, सोसायटी के लिए यह उचित होगा कि वह चार्टर्ड इंजीनियरों की मदद से उक्त भूमि का एक खाका तैयार करे और उसे अनुमोदन के लिए उपयुक्त अधिकारियों को प्रस्तुत करे और ऐसे अनुमोदित खाके के आधार पर, बिक्री के लिए या निर्माण की जाने वाली इकाइयों के रूप में भूखंडों की उपलब्धता के आधार पर, सोसाइटी के सदस्यों की वरिष्ठता के आधार पर निर्माण के किसी भी भूखंड या इकाई का ऐसा आवंटन करने का निर्णय करेगी।

(ix) एक बार जब सर्वेक्षण में भूमि का ऐसा वितरण सोसायटी द्वारा किया जाना है, तो यह सुनिश्चित करना सोसाइटी का दायित्व होगा कि उसके सदस्यों द्वारा किसी भी रूप में जमा की गई राशि, जिसे उप-कानून के तहत जमा के रूप में माना जाना है, को

ऐसी जमा राशि की तारीख से ऐसी जमा राशि पर उपार्जित ब्याज के साथ ध्यान में रखा जाएगा और उन सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल का निर्णय करते समय क्रेडिट दिया जाएगा जो भूमि/आवास इकाई के आवंटन के लिए पात्र होंगे, उस मूल्य के आधार पर जो चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा की गई ऐसी जमाओं को ऋण देते समय, यदि व्यक्तिगत सदस्यों से कोई अतिरिक्त राशि एकत्र की जानी बाकी रहती है, तो ऐसे आवंटन करने से पहले ऐसे भुगतान की वसूली की जाएगी और ऐसे सदस्य निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहने या आवंटन के लिए अपना अधिकार छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में, यह सोसायटी को उप-कानूनों के अनुसार उचित तरीके से निर्णय लेना होगा कि बचे हुए 36 भूखंड/आवास इकाई को वरिष्ठता में अगले सदस्य को कैसे आवंटित किया जाना चाहिए, जिसके लिए इस तरह के आवंटन का दावा करने का अधिकार उपलब्ध होगा।

(x) यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी सदस्य या तो संस्थापक सदस्य या बाद के सदस्य अपने निवेश के आधार पर इस आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके निवेश ने सोसायटी को भूमि खरीदने में सक्षम बनाया या उनका निवेश मूल्य में या किसी अन्य आधार पर अधिक था।

(xi) आवास परियोजनाओं के लिए किया जाने वाला कोई भी अन्य निवेश, उपनियम 2 के अनुसार सोसायटी के उद्देश्य के अनुसार, सोसाइटी द्वारा भविष्य में उपनियमों के अनुसार और साथ ही साथ हाउसिंग सोसाइटी को नियंत्रित करने वाले अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(xii) चूंकि उपरोक्त अभ्यास इस निर्णय में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, इसलिए हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई भी आगे

का आदेश/निर्देश केवल इस न्यायालय द्वारा और इस देश में किसी अन्य न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।

41. जहाँ तक हमारा निष्कर्ष और निर्देश विभिन्न कारकों पर आधारित थे जैसे कि उपनियमों की व्याख्या, उच्च न्यायालय के निष्कर्षित आदेश और हमारे सामने रखे गए अभिलेखों के आधार पर निकाले गए अन्य अनियंत्रित तथ्यों के साथ-साथ हमारे दिनांकित 04.09.2012 के आदेश के अनुसार आंध्र प्रदेश की सहकारी समिति के 37 कुलसचिव की रिपोर्ट, हमारा विचार है कि इन अपीलों में आरोपित आदेश कायम नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा, हम पाते हैं कि बहुत सारे कारक जो हमारे ध्यान में लाए गए हैं, जिनके विवरण की इस न्यायालय द्वारा सराहना की जा सकती है, इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों में नहीं पाए जा सके।

42. इसलिए, हम इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों को दरकिनार करते हुए यह अभिनिर्धारित करते हैं कि पैराग्राफ 40 में निहित निर्देश अकेले इस मामले को नियंत्रित करेंगे। हमारे उपरोक्त आदेशों के आलोक में, हम पाते हैं कि 2010 की अवमानना याचिका (सी) सं॰ 302 और 2010 की एसएलपी (सी) सं॰ 4679 में 2011 की 251 में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अवमानना याचिकाएं बंद कर दी गई हैं। इस संदर्भ में, हमें कानूनी उक्ति 'ब्याज पुनः प्रकाशन और अंत तक कानूनी कार्यवाही' की याद दिलाई जाती है, जिसका अर्थ है कि मुकदमेबाजी का अंत राज्य के सामान्य कल्याण के लिए है। इसलिए, हम सहकारी समिति के कहने पर इस चिरस्थायी मुकदमे को समाप्त करने के लिए उपरोक्त निर्देश पारित करते हैं। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलों की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।